



विकास को पुनर्परिभाषित करना: भारत का संशोधित जीडीपी अनुमान और नई कार्य योजना

27 फरवरी, 2026

मुख्य बिंदु

- 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.6% अनुमानित है, जो 2024-25 में दर्ज की गई 7.1% से अधिक है।
- भारत की बदलती आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए जीडीपी अनुमानों का आधार वर्ष 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 कर दिया गया है।
- संशोधित जीडीपी श्रृंखला, एएसयूएसई, पीएलएफएस, जीएसटी, पीएफएस आदि जैसे नए और बेहतर डेटा स्रोतों को एकीकृत करके अनुमान को और मजबूत बनाती है।

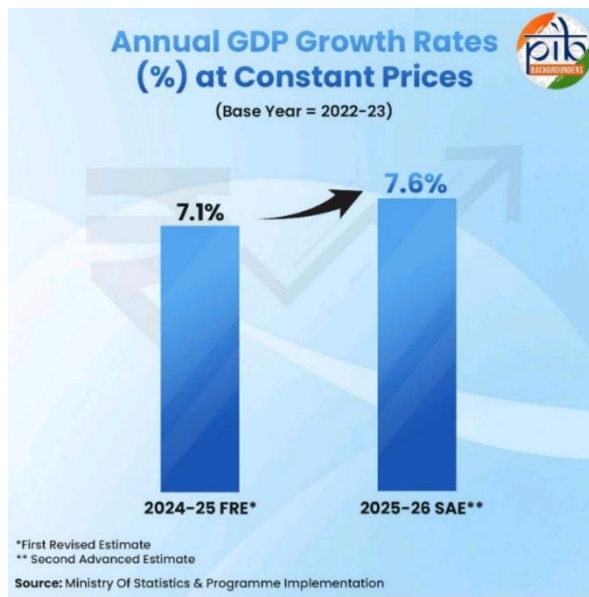
प्रस्तावना

भारत के विकास पथ को न केवल आर्थिक प्रदर्शन बल्कि इसकी सांख्यिकीय प्रणालियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता द्वारा भी आकार दिया जा रहा है। इस दिशा में, आधार वर्ष 2022-23 के साथ भारत के नवीनतम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों का व्यापक अवलोकन, पिछले वित्तीय वर्षों की तुलना में अर्थव्यवस्था की विकसित गति को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक वार्षिक जीडीपी वृद्धि 7.6% अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज 7.1% से अधिक है, जबकि मौजूदा कीमतों पर मापी गई जीडीपी, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 8.6% बढ़ने का अनुमान है। इसके भीतर, विनिर्माण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2025-26 दोनों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है, जो अर्थव्यवस्था के लचीले प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों ने समग्र आर्थिक प्रदर्शन को मजबूत किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में विकासदर 9.0% से अधिक दर्ज की गई है। साथ ही, 'व्यापार, मरम्मत, होटल, परिवहन,

संचार और प्रसारण और भंडारण से संबंधित सेवाएं' क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर 10.1% की वृद्धि दर दर्ज की।

भारत की आर्थिक प्रगति में लगातार बढ़ोतरी का असर तिमाही नतीजों में भी दिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर (Q3) अवधि के लिए स्थिर कीमतों पर वास्तविक जीडीपी ₹84.54 लाख करोड़ अनुमानित है, जो 7.8% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 7.1% और वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 7.4% से उत्तरोत्तर तेज हो गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर लचीलापन और मजबूती को रेखांकित करती है।

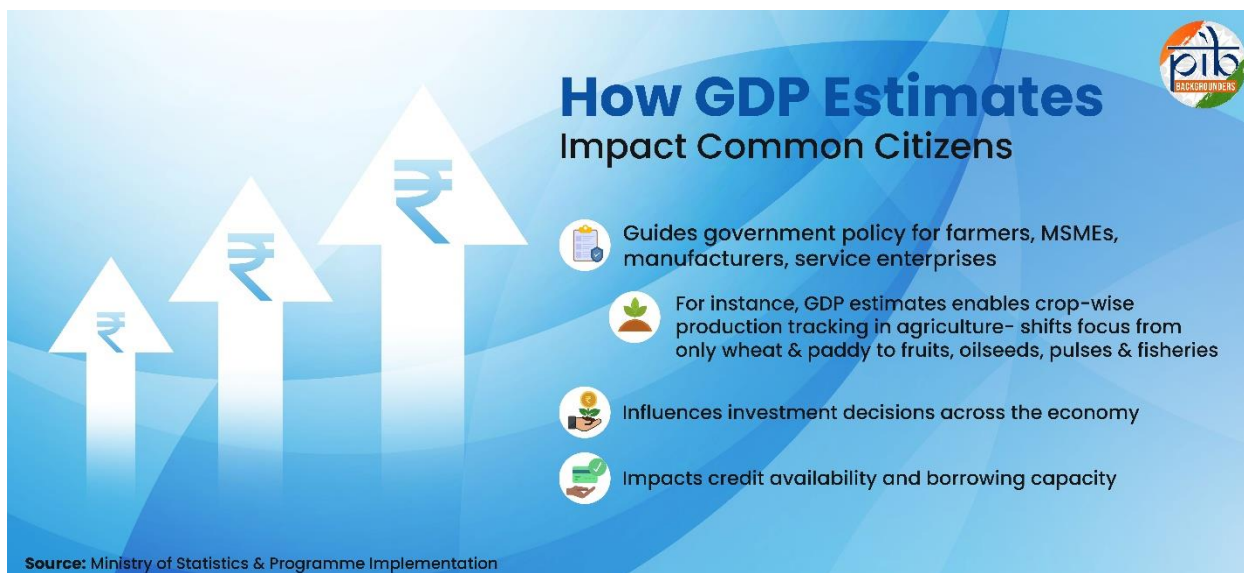


जीडीपी एक लेखांकन अवधि में किसी देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है।

जीडीपी अनुमानों की नई श्रृंखला में पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की प्रगति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। यह संकलन बेंचमार्क-संकेतक पद्धति पर आधारित है जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए गणना किए गए अनुमानों को विभिन्न आर्थिक और संस्थागत क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाते हुए प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके निकाला जाता है।

भारत की बदलती गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी अनुमान को पुनः व्यवस्थित करना

जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार और समग्र स्वास्थ्य का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है। समय के साथ जीडीपी में बदलावों पर नज़र रखकर, कोई यह आकलन कर सकता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या सिकुड़ रही है और जीवन स्तर में सुधार के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकाल सकती है। इसलिए, **नीति निर्माता, व्यवसाय और वित्तीय संस्थान आर्थिक योजना और निर्णय लेने के मार्गदर्शन के लिए जीडीपी रुझान** पर भरोसा करते हैं।



समय-समय पर तुलना को सार्थक बनाने के लिए, **जीडीपी अनुमान सुसंगत कार्यप्रणाली, डेटा स्रोतों और आधार वर्षों पर आधारित होना चाहिए**। इसलिए माप ढाँचे में कोई भी संशोधन निरंतरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए।

तिमाही जीडीपी अनुमानों की गणना

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 और आईएमएफ के त्रैमासिक राष्ट्रीय लेखा नियमावली 2017 के अनुसार विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली मानक पद्धति, बेंचमार्क-संकेतक का उपयोग करके त्रैमासिक जीडीपी अनुमानों की गणना करते हैं। यह पद्धति इस प्रकार कार्य करती है:

- वार्षिक जीडीपी अनुमान एक संदर्भ बिंदु/मानदंड के रूप में कार्य करते हैं।
- इन अनुमानों पर मासिक या त्रैमासिक संकेतकों जैसे उच्च-आवृत्ति डेटा लागू किए जाते हैं।

इसे स्वीकार करते हुए, भारत की सांख्यिकीय प्रणाली में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए व्यापक आधुनिकीकरण किया गया है। प्रमुख सुधारों में सकल घरेलू उत्पाद और मूल्य सूचकांकों के आधार वर्षों को संशोधित करना, अनौपचारिक और सेवा क्षेत्रों की माप को मजबूत करना, श्रम बाजार के आंकड़ों में सुधार करना, उन्नत सर्वेक्षण विधियों और प्रौद्योगिकी को अपनाना और व्यापक हितधारक जुड़ाव के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है।

सामूहिक रूप से, इन सुधारों का उद्देश्य भारत के आधिकारिक आंकड़ों की समयबद्धता, गहराई और विश्वसनीयता को बढ़ाना है , जिससे साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की नींव मजबूत हो।

डिकोडिंग आधार वर्ष

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय, उत्पादन और व्यय समुच्चय पर डेटा प्रदान करता है, **आधार वर्ष उसके लिए** संदर्भ वर्ष है जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक विकास की गणना के लिए किया जाता है।

आधार वर्ष संशोधनों का पुनर्निर्धारण एवं आवृत्ति

भारत की उभरती आर्थिक संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए जीडीपी आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करना एक प्रमुख सुधार है।

आधार वर्ष का पुनर्निर्धारण अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित और बेहतर आंकड़ों का उपयोग करके आधार वर्ष को अद्यतन करने की प्रक्रिया है। नया आधार फिर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और उसके घटकों के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जैसे प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

जीडीपी आधार वर्ष को संशोधित कर वित्त वर्ष 2022-23 क्यों किया गया है?

अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों को प्रतिबिंबित करने और आर्थिक अनुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए आधार वर्ष को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस तरह के अपडेट पद्धतिगत सुधार और अधिक व्यापक और विश्वसनीय डेटा स्रोतों के एकीकरण की अनुमति देते हैं।

पिछले दशक में, उपभोग पैटर्न और निवेश व्यवहार में बदलाव के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था काफी विकसित हुई है। रिबेसिंग जीडीपी और संबंधित सूचकांकों को उभरते क्षेत्रों के योगदान, सापेक्ष कीमतों में बदलाव और प्रौद्योगिकी और उत्पादकता में प्रगति को बेहतर ढंग से पकड़ने में सक्षम बनाता है। इसने तेजी से डिजिटलीकरण ने उच्च-आवृत्ति डेटा की उपलब्धता का विस्तार किया है, जिससे राष्ट्रीय खातों की सटीकता मजबूत हुई है। वास्तविक समय प्रणालियाँ जैसे **ई-वाहन (वाहन पंजीकरण), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), और जीएसटी नेटवर्क** अब विस्तृत आर्थिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं जो जीडीपी अनुमानों को मजबूत करती हैं।

इसके अलावा, समय-समय पर होने वाले संशोधन संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखण का भी समर्थन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत का सांख्यिकीय ढांचा पद्धतिगत रूप से सुदृढ़ और विश्व स्तर पर तुलनीय बना रहे, विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था माप और आपूर्ति-उपयोग तालिकाओं जैसे क्षेत्रों में।

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2022-23 को नया आधार वर्ष चुना गया है क्योंकि यह 2019-2021 की व्यवधानों के बाद की सबसे हालिया "सामान्य" अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2019-20 और 2020-21 कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिसने अस्थायी रूप से उपभोग के रुझानों और औद्योगिक गतिविधियों को विकृत कर दिया था।

Revising India's National Accounts Base Year



What's Changing?

GDP
New Base Year
2022-23

CPI
New Base Year
2024

IIP
New Base Year
2022-23

Why Rebasing?



Economic Change
New sectors &
consumption patterns



Global Standards
Align with UN
Best Practices



Better Data
GST, PFMS, e-Vahan,
HCES

Source: Ministry of Statistics & Planning Implementation (MoSPI), Government of India

भारत के सकल घरेलू उत्पाद अनुमान का आधुनिकीकरण

संशोधित जीडीपी श्रृंखला कई नए और बेहतर डेटा स्रोतों को एकीकृत करके अनुमान को मजबूत करती है। सुधार प्रॉक्सी संकेतकों पर निर्भरता को कम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय आय अनुमान अर्थव्यवस्था की विकसित संरचना को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं।

नई श्रृंखला में डेटा स्रोतों का उपयोग किया जा रहा है

घरेलू क्षेत्र का मापन: पहले, घरेलू क्षेत्र के अनुमान बड़े पैमाने पर मानक सर्वेक्षणों या प्रॉक्सी संकेतकों के बीच विकास दर पर निर्भर करते थे। संशोधित श्रृंखला में, वास्तविक स्तर के अनुमान नियमित वार्षिक सर्वेक्षणों जैसे अनिगमित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किए जा रहे हैं। यह बदलाव क्षेत्र की गतिशीलता का अधिक सटीक और समय पर आकलन करने में सक्षम बनाता है।

जीएसटी डेटा का उपयोग: जीएसटी डेटा राज्यों में अखिल भारतीय निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के अनुमानों के आवंटन का समर्थन करता है और वार्षिक खातों में -सत्यापन के लिए उपयोग किया जाता है। यह त्रैमासिक अनुमान में और त्रैमासिक राष्ट्रीय खातों के संकलन में एक संकेतक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। नई श्रृंखला विनिर्माण और गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रों में जीएसटी डेटा का व्यापक और अधिक व्यवस्थित उपयोग करती है।

ई-वाहन डेटाबेस: सड़क परिवहन सेवाओं से संबंधित निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का अनुमान लगाने के लिए ई-वाहन पोर्टल के डेटा का उपयोग किया जा रहा है। पीएफसीई देश के निवासी परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम खपत पर किया गया व्यय है।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस): पीएफएमएस डेटा का उपयोग केंद्र सरकार के खातों को संकलित करने और उन्हें राज्यों में वितरित करने के लिए किया जा रहा है। यह संशोधित अनुमान (आरई) पर निर्भर होने के बजाय पहले संशोधित अनुमान (एफआरई) चरण में वास्तविक व्यय आंकड़ों के उपयोग को सक्षम बनाता है। पीएफएमएस एक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली है जो एंड-टू-एंड डिजिटल भुगतान, रसीदों का संग्रह, लेखांकन, समाधान और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मॉड्यूल प्रदान करती है।

हाल के अध्ययनों का समावेश: अनुमान की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल के विशेषज्ञ अध्ययनों के आधार पर अद्यतन दरों और अनुपातों को शामिल किया गया है। इसमें शामिल है:

- भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान (कृषि) द्वारा घास और चारे का अध्ययन
- केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा मत्स्य पालन अध्ययन
- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा दूध और दूध उत्पादों पर अध्ययन (पीएफसीई के लिए)
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा परिवहन सेवाओं पर अध्ययन (पीएफसीई के लिए)

इसके साथ ही ये संवर्द्धन राष्ट्रीय आय अनुमानों की मजबूती, व्यापकता और विश्वसनीयता में सुधार करते हैं।

नई जीडीपी श्रृंखला में प्रमुख पद्धतिगत सुधार

संशोधित जीडीपी श्रृंखला सटीकता, स्थिरता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए कई पद्धतिगत संवर्द्धन प्रस्तुत करती है:

परिष्कृत अपस्फीति तकनीक: दोहरी अपस्फीति अब विनिर्माण और कृषि में लागू की जाती है, जबकि एकल एकस्ट्रपलेशन का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। एकल अपस्फीति को बंद कर दिया गया है।

डिफ्लेटर्स को अधिक विस्तृत स्तर पर लागू किया जाता है, जिसमें 260 से अधिक आइटम-स्तरीय सीपीआई सूचकांक शामिल होते हैं।

आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं (एसयूटी) का एकीकरण: उत्पादन और व्यय-आधारित जीडीपी अनुमानों के बीच विसंगतियों को कम करने के लिए एसयूटी ढांचे को राष्ट्रीय खातों के साथ जोड़ा गया है। कुल मांग के साथ कुल आपूर्ति का मिलान करके, यह दृष्टिकोण आंतरिक स्थिरता में सुधार करता है।

एक डिफ्लेटर का उद्देश्य समान उत्पादों के लिए दो समय अवधियों के बीच कीमतों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को शुद्ध मूल्य परिवर्तन में विभाजित करना है।

अद्यतन दरें और अनुपात: विशेषज्ञ संस्थानों के सहयोग से एमओएसपीआई द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण निष्कर्षों और अध्ययनों का उपयोग करके संकलन मापदंडों को संशोधित किया गया है।

बहु-गतिविधि निगमों का पृथक्करण: पहले, विविध उद्यमों द्वारा जोड़ा गया मूल्य उनकी प्रमुख गतिविधि को सौंपा गया था। एमजीटी-7/7ए फाइलिंग (जो गतिविधि-वार टर्नओवर शेयरों की रिपोर्ट करती है) की उपलब्धता के साथ, जोड़ा गया मूल्य अब गतिविधियों में अधिक सटीक रूप से वितरित किया जाता है।

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का बेहतर अनुमान:

घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के उन्नत उपयोग, उत्पादन और प्रशासनिक डेटा से प्रत्यक्ष अनुमान और वस्तु प्रवाह दृष्टिकोण को मिलाकर एक मिश्रित पद्धति अपनाई गई है। अद्यतन सीओआईसीओपी 2018 वर्गीकरण भी लागू किया गया है। उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग का वर्गीकरण (सीओआईसीओपी) घरेलू व्यय का अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण है।

संशोधित ढांचे का क्षेत्रीय कवरेज

कई क्षेत्र-विशिष्ट सुधारों के साथ, संशोधित त्रैमासिक संकलन ढांचे को क्षेत्रीय वर्गीकरण, अपस्फीति रणनीतियों और अनुमान प्रथाओं के संदर्भ में वार्षिक राष्ट्रीय लेखा पद्धति के साथ अधिक निकटता से जोड़ा गया है। सामंजस्य त्रैमासिक और वार्षिक जीडीपी और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) अनुमानों के बीच अधिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

विशेष रूप से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), इकाई मूल्य सूचकांक आदि जैसे डिफ्लेटर का उपयोग पुरानी श्रृंखला में समग्र स्तर से नई श्रृंखला में आइटम-समूह स्तर पर जाकर अधिक विस्तृत स्तर पर किया जा रहा है।

जीडीपी अनुमान में किराये पर लिए गए घरेलू कामगारों को शामिल करना

किराए पर लिए गए घरेलू कामगारों की सेवाओं को "घरेलू कर्मियों के नियोक्ता के रूप में परिवारों की गतिविधियों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जीडीपी अनुमान में शामिल किया गया है। उनके योगदान की गणना ऐसे श्रमिकों की संख्या और उनके वेतन पर वार्षिक आधार पर डेटा का उपयोग करके की जाती है।

संशोधित जीडीपी श्रृंखला में डिजिटल, प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था गतिविधियों को शामिल करना

कॉर्पोरेट क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं, मध्यस्थ प्लेटफार्मों और संबंधित गतिविधियों को पहले से ही कवर किया गया था एमसीए-21 फाइलिंग के माध्यम से, ई-गवर्नेंस पहल जो दस्तावेजों को दाखिल करने, कंपनियों के पंजीकरण और एक सुरक्षित इंटरैक्टिव पोर्टल के माध्यम से कॉर्पोरेट जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच सहित सभी रजिस्ट्री संबंधित सेवाओं की उपलब्धता प्रदान करती है। नई श्रृंखला में अनिगमित उद्यम, स्व-रोज़गार व्यक्ति और अनौपचारिक श्रमिक शामिल हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में उनके योगदान को वार्षिक आधार पर अधिक सटीक रूप से दर्ज किया जा सकता है।

सामान्य सरकारी क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए प्रमुख डेटा स्रोत

सामान्य सरकारी क्षेत्र के अनुमान मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों - जैसे कि रसीद बजट और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की विस्तृत मांग - के साथ-साथ स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों के वार्षिक खातों का उपयोग करके संकलित किए जाते हैं।

नई श्रृंखला में इन अनुमानों को मजबूत करने के लिए कई सुधार शामिल हैं। इनमें शामिल हैं-

- पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के निरंतर संचालन के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के कार्यान्वयन के लिए समायोजन
- मकान किराया भत्ता (एचआरए) के स्थान पर सरकार द्वारा प्रदत्त आवास का आरोप।
- स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों की बेहतर कवरेज
- स्थिर कीमतों पर उत्पाद सब्सिडी का अनुमान लगाने के लिए वॉल्यूम एक्सट्रपलेशन पद्धति को अपनाना।

इसके साथ ही ये परिशोधन सामान्य सरकारी क्षेत्र के अनुमानों की सटीकता और व्यापकता को बढ़ाते हैं।

आपूर्ति और उपयोग तालिका ढांचे में प्रमुख विसंगति को हल करना

एसयूटी बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कैसे होता है। आपूर्ति पक्ष पर, वे दिखाते हैं कि उत्पाद अर्थव्यवस्था में कैसे प्रवेश करते हैं - या तो घरेलू उत्पादन या आयात के माध्यम से। उपयोग पक्ष में, वे दिखाते हैं कि इन उत्पादों का उपभोग कैसे किया जाता है - उद्योगों द्वारा मध्यवर्ती इनपुट के रूप में, घरों द्वारा अंतिम उपभोग, घरों (एनपीआईएसएच) और सरकार की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संस्थान, सकल पूंजी निर्माण, या निर्यात।

प्रत्येक उत्पाद के उपयोग के साथ आपूर्ति को जोड़कर, एसयूटी ढांचा जीडीपी अनुमान के लिए उत्पादन, आय और व्यय दृष्टिकोण को एकीकृत और संतुलित करने के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करता है।

हालाँकि, डेटा कवरेज में अंतर, डेटा उपलब्धता में समय अंतराल, अग्रिम अनुमानों के लिए प्रॉक्सी संकेतकों पर निर्भरता और अनुमान विधियों में भिन्नता के कारण इन दृष्टिकोणों के बीच विसंगतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 (एसएनए 2008), जो एसएनए 2025 में जारी है, ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोणों की सिफारिश करती है:

- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधिकारिक जीडीपी अनुमानों के साथ-साथ सांख्यिकीय विसंगति को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें।
- आपूर्ति और उपयोग तालिका ढांचे का उपयोग करके उत्पादन/आय और उत्पादन अनुमानों का मिलान करें, जो डेटासेट में स्थिरता को मजबूत करता है।

नई जीडीपी श्रृंखला में, एसयूटी ढांचे को संकलन प्रक्रिया में व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जा रहा है। "उत्पाद-संतुलन" सिद्धांत को लागू करके (यह सुनिश्चित करते हुए कि कुल आपूर्ति कुल उपयोग के बराबर है), रूपरेखा उत्पादन और व्यय अनुमानों के बीच अंतर को सुलझाने में मदद करती है। परिणामस्वरूप, अंतिम अनुमानों में सांख्यिकीय विसंगतियों का समाधान हो जाता है, जिससे आंतरिक रूप से सुसंगत और अधिक विश्वसनीय जीडीपी आंकड़े सामने आते हैं।

जीएसडीपी अनुमान में स्थिरता और पद्धतिगत मजबूती सुनिश्चित करना

एमओएसपीआई के तहत एनएसओ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के अनुमान के लिए दिशानिर्देश जारी करता है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटीएस) को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जीएसडीपी को राष्ट्रीय खातों के अनुरूप समान परिभाषाओं, अवधारणाओं और पद्धतियों का उपयोग करके संकलित किया गया है। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) राज्य-विशिष्ट डेटा का उपयोग करके अपने जीएसडीपी अनुमान तैयार करते हैं, जो बड़े पैमाने पर सामान्य डेटा स्रोतों से लिया जाता है।

जीएसडीपी एक वर्ष के दौरान राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है।

कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों के साथ नए आधार पर जीएसडीपी श्रृंखला शुरू की जाएगी

नए आधार वर्ष 2022-23 के साथ जीडीपी जारी होने के बाद, एनएसओ, मोएसपीआई आवश्यक कार्यप्रणालीगत परिवर्तनों और सुधारों के बारे में जानकारी देगा ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने जीएसडीपी अनुमानों को तदनुसार संशोधित कर सकें।

- कुछ क्षेत्रों या उप-क्षेत्रों के लिए आवंटन-आधारित विधियों में कमी और प्रत्यक्ष अनुमान विधियों का उपयोग।
- निश्चित अनुपातों और परोक्ष संकेतकों पर निर्भरता में कमी।
- राज्य-स्तरीय आर्थिक आंकड़ों का बेहतर उपयोग और राज्यों में कार्यप्रणाली की एकरूपता में वृद्धि।

भविष्य की रूपरेखा

जीडीपी अनुमानों के लिए आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित किए जाने, सीपीआई के आधार वर्ष को 2024 में संशोधित किए जाने और आईआईपी को 2022-23 में संशोधित किए जाने के साथ, भारत की सांख्यिकी प्रणाली का व्यापक आधुनिकीकरण हो रहा है। इसी गति को जारी रखते हुए, उत्पादक मूल्य

सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष का संशोधन भी प्रगति पर है। अद्यतन डब्ल्यूपीआई उपलब्ध होने तक, मौजूदा डब्ल्यूपीआई का उपयोग अपस्फीति सूचकांक के रूप में किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, सामाजिक-आर्थिक संस्थान (एमओएसपीआई) निकट भविष्य में उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को शामिल करने की योजना बना रहा है। पीपीआई उत्पादकों द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की दर को मापता है।

आगामी महीनों में जारी होने वाले अन्य आंकड़ों में शामिल हैं-

- अनुमानों के संकलन में प्रयुक्त कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों को एमओएसपीआई के प्रकाशन 'स्रोत और विधियाँ' में प्रस्तुत किया जाना है और इसके अगले कुछ महीनों में जारी होने की संभावना है।
- पिछले वर्षों के डेटा दिसंबर 2026 तक जारी होने की उम्मीद है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, संशोधित कार्यप्रणाली का उपयोग करके पिछले आधार वर्ष तक अनुमानों की पुनर्गणना की जाएगी और फिर श्रृंखला को 1950-51 तक विस्तारित करने के लिए उन्हें विखंडित स्तर पर जोड़ा जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) अनुमानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सांख्यिकीय ढांचे, 2008 राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए 2008) के अनुसार संकलित करता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा एसएनए 2025 को अपनाने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ - जिसके 2029-30 के आसपास वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने की उम्मीद है - भारत अपने अगले आधार वर्ष संशोधन में अद्यतन मानक के अनुरूप होने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) का पालन करने वाले देश के रूप में, भारत सांख्यिकीय गुणवत्ता और पारदर्शिता के वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों का अनुपालन करता है। संशोधित जीडीपी श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है।

निष्कर्ष

वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक जीडीपी में 7.6% की वृद्धि का अनुमान है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत और सतत विस्तार होने की संभावना है। यह मजबूत प्रदर्शन भारत की विकास गति को सुदृढ़ करता है और उच्च उत्पादकता, लचीलापन और समावेशी विकास से चिह्नित विकसित भारत की परिकल्पना

को प्राप्त करने की दिशा में इसके पथ को मजबूत बनाता है। इस संदर्भ में, जीडीपी आधार वर्ष को 2022-23 में संशोधित करना, तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं के अनुरूप भारत के राष्ट्रीय लेखा को संरेखित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर डेटा स्रोतों को एकीकृत करके, कार्यप्रणालीगत ढाँचों को मजबूत करके, उभरते क्षेत्रों के कवरेज का विस्तार करके और एसयूटी ढाँचे के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाकर, नई श्रृंखला आर्थिक गतिविधि का अधिक सटीक, सुसंगत और व्यापक माप प्रदान करती है। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली सटीकता, तुलनीयता और वैश्विक संरेखण के उच्च मानकों की ओर अग्रसर है। ये सभी प्रयास आधिकारिक आंकड़ों की विश्वसनीयता को मजबूत करते हैं और सूचित नीति निर्माण और सतत आर्थिक नियोजन के लिए एक ठोस आधार के रूप में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करते हैं।

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2129126®=3&lang=2>

[https://www.mospi.gov.in/uploads/latestReleases/latest_release_1771587946242_979ab984-ab1d-4f5f-b412-](https://www.mospi.gov.in/uploads/latestReleases/latest_release_1771587946242_979ab984-ab1d-4f5f-b412-66cff02f8e9d)

[66cff02f8e9d](https://www.mospi.gov.in/uploads/latestReleases/latest_release_1771587946242_979ab984-ab1d-4f5f-b412-66cff02f8e9d) Press note for Release of Report of Committee on Constant Price Estimates.pdf

वित्त मंत्रालय

<https://pfms.nic.in/Home.aspx>

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय

<https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?relid=52614®=3&lang=2>

यूरोपियन यूनियन

[https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP -
What is gross domestic product \(GDP\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:GDP-_What_is_gross_domestic_product_(GDP))

ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया

<https://www.data.gov.in/catalog/final-consumption-expenditure-constant-prices>

पीआईबी अभिलेखागार

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219549®=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155121&ModuleId=3®=3&lang=2>

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

<https://www.ons.gov.uk/economy/inflationandpriceindices/methodologies/deflatorsandhowweusetheconomicestimates>

संयुक्त राष्ट्र

https://unstats.un.org/unsd/classifications/unsdclassifications/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एनएस